



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-13042020-219045  
CG-DL-E-13042020-219045

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]  
No. 94]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2020/चैत्र 24, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2020/CHAITRA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

मामला सं. (एसजी) 03/2019

विषय : भारत में "फिनोल" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – जांच की समाप्ति।

फा. सं. 22/3/2019-डीजीटीआर.—क. परिचय

समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै. दीपक फेनोलिक लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार महानिदेशक के समक्ष एक आवेदन (याचिका) प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध वस्तु के बड़े हुए आयातों तथा फेनोल के ऐसे बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर परिणामी क्षति और गंभीर क्षति के खतरे का आरोप लगाते हुए भारत में "फेनोल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने और रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. महानिदेशक ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 23 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 23/3/2019-डी जी टी आर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसमें नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध रक्षोपाय जांच की शुरुआत की गई ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई है और क्या बढ़े हुए आयातों के कारण समान और/या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और/या गंभीर क्षति होने का खतरा है। जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार आवेदक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) की उपधारा (6) के खंड (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

#### **ख. प्रक्रिया**

3. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) तथा (3) के अनुसार जांच शुरुआत की सूचना (एनओआई) दिनांक 23 अगस्त, 2019 की एक प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश (एनसीवी) की एक प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में केन्द्र सरकार और भारत में स्थित प्रमुख निर्यातक देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों तथा उक्त आवेदन में उल्लिखित हितबद्ध पक्षों को भेजी गई थी। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत यथाविहित प्रश्नावली विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी गई थी तथा उनसे एनओआई जारी किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

4. इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत यथा विहित निर्यातकों/ आयातकों/ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तरित की जाने वाली प्रश्नावली को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि वे जांच शुरुआत की सूचना जारी हाने के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।

5. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तरों में निम्नलिखित निर्यातकों/ विदेशी उत्पादकों और निर्यातक देशों की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

- i. मै. मित्सुर्ड एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई. लि.
- ii. ब्यूरो ऑफ फॉरन ट्रेड आर्थिक कार्य मंत्रालय, चीन गणराज्य (ताइवान)
- iii. मै. फार्मोसा कैमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन
- iv. किंगडम ऑफ सऊदी अरब
- v. ब्राजील गणराज्य परिसंघ का दूतावास
- vi. मै. कुम्हो पी एंड बी कैमिकल्स, कोरिया गणराज्य
- vii. लोक उद्योग प्राधिकरण, स्टेट ऑफ कुवैत
- viii. मै. चांग चुन प्लास्टिक्स कं. लि., ताइवान
- ix. भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधि
- x. मै. एल.जी. कैम लि.
- xi. कोरिया पैट्रोकैमिकल इडस्ट्री एसोसिएशन
- xii. मै. पी टी टी फेनोल्स कंपनी लिमिटेड
- xiii. मै. मित्सुर्ड फेनोल्स सिंगापुर पीटीई. लि.
- xiv. मै. सुमिटोमो कैमिकल एशिया पीटीई. लि.
- xv. मै. चांग चुन कैमिकल (जियांगशु) कं. लि.
- xvi. इंडोनेशिया की सरकार
- xvii. मै. रहोदिया पोलियामिंडा ए इस्पेशियालिडाइस एस/ए

6. निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और उनके संघों से हितबद्ध पक्षकार माने जाने पर विचार करने और/या अनुरोध/आयातक प्रश्नावली के उत्तर संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे ।

- क. मै. विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
- ख. मै. एग्जिम कॉर्प
- ग. मै. मेघमनी ऑर्गेनिक्स लि.
- घ. मै. वरसालिस एसपीए
- ड. मै. सेंचुरी प्लाईबोर्डस (इंडिया) लिमिटेड
- च. मै. रविध रिफाइनिंग एंड पैट्रोकैमिकल कंपनी
- छ. मै. अतुल लि.
- ज. मै. सी. जे. शाह एंड कंपनी
- झ. मै. एकिन कैमिकल्स प्रा. लि.
- ञ. मै. जुपिटर डाइकैम प्रा. लि.
- ट. मै. हजेल मर्केन्टाइल लिमिटेड
- ठ. मै. हरेशकुमार एंड कं.
- ड. मै. हरेश पैट्रोकैम प्रा. लि.
- ठ. फैडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री
- ण. अतुल लि.
- त. मेघमनी ऑर्गेनिक्स लि.

7. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19, अप्रैल से जून 2019 (2019-20 की पहली तिमाही) है । आवेदकों ने 2019-20 की पहली तिमाही में आयातों में अचानक वृद्धि होने का दावा किया है ।

8. वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई आयात मात्रा वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के आंकड़ों पर आधारित थी, परंतु 2019-20 की पहली तिमाही के लिए आयात मात्रा एक गौण स्रोत से ली गई थी । जांच की शुरूआत के पश्चात प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए विचारित संपूर्ण अवधि हेतु डी जी सी आई एंड एस से सौदावार आंकड़े प्राप्त किए हैं ।

9. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा गया था ।

10. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार महानिदेशक ने 4 दिसंबर, 2019 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया था । सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों से मौखित रूप से प्रस्तुत विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था ।

11. एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकार के लिखित अनुरोधों के संबंध में खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था ।

#### **ग. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आयातों में ऐसी दशा में वृद्धि हुई है कि घरेलू उद्योग को उससे क्षति हुई है ।
- ख. चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने, चीन में नई क्षमताओं, वैश्विक अति आपूर्ति, भारत में नई क्षमताओं और यूएस-चीन व्यापार समस्याओं जैसे कारकों से आयातों में यह वृद्धि हुई है ।

- ग. संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है।
- घ. भारत में संबद्ध वस्तु के आयात फेनोल के मांग के अनुसार अनिवार्य मात्राओं से काफी अधिक हैं।
- ड. बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, विक्री कीमतों, मालसूचियों और विक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- च. विल्कुल हाल की अवधि में कीमतों में तेजी से गिरावटों के साथ आयातों में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा हो गया है।

**घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्ष 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के लिए याचिका में प्रदत्त आयात मात्रा डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित है परंतु 2019-20 की पहली तिमाही के लिए आयात मात्रा अप्रकट गौण ग्रोत से ली गई है और इसलिए सत्यापन योग्य नहीं है तथा अविश्वसनीय है। डी जी एफ टी के डाटा बेस से प्राप्त फेनोल की आयात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए काफी कम आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। अतः आयातों में ऐसी कोई तीव्र वृद्धि नहीं हुई है, जो भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों संबंधी रक्षोपाय जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराती हो।
- ख. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि रक्षोपाय जांच के लिए आयातों में वृद्धि विल्कुल हाल की, पर्याप्त रूप से अचानक, पर्याप्त रूप से तीव्र और इतनी अधिक होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो। यद्यपि, वर्ष वार आधार पर 2016-17 की तुलना में आयातों में 1% की मामूली वृद्धि हुई है, 2017-18 तथा 2018-19 के बीच आयातों में 20% की भारी गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। अधिकांश आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक रूझान और कार्य निष्पादन में सुधार प्रदर्शित होता है।
- घ. अभिज्ञात घटनाक्रम में से किसी को भी गैट के अनुच्छेद XIX (1) (क) के अनुसार “अप्रत्याशित” नहीं माना जा सकता है। चीन जैसे प्रमुख खपत बाजारों द्वारा केवल व्यापार उपचारात्मक उपायों को लगाए जाने को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है।
- ड. आवेदन अधूरा है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा कोई समायोजन योजना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- च. घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री, स्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और कर्मचारियों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने नियोजित पूँजी पर आय तथा लाभ में भी भारी सुधार प्रदर्शित किया है।
- छ. दीपक फैनोलिक्स द्वारा उठाई गई कोई कथित क्षति गंभीर समस्याओं के कारण हो सकती है और उसके लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एस आई ग्रुप, जिसने पूर्व में फेनोल संबंधी व्यापार उपचार जांचों में सदैव भागीदारी की है और जिसका भारत में उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा बनता है, इस याचिका में भागीदार नहीं हैं।
- ज. दीपक फैनोलिक्स जांच अवधि अर्थात् पी ओ आई के 31 महीनों के लिए अधिकांश अवधि में मौजूद नहीं था। ऐसे घरेलू उद्योग की क्षति का कोई उचित आकलन नहीं किया जा सकता है जिसका एक घटक पी ओ आई के पहले 31 महीनों में अस्तित्व में नहीं था।
- झ. एच ओ सी एल को काफी लंबे समय से सतत प्रचालन के लिए कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता, संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए निधियों की कमी, देयताओं के निपटान के लिए अन्य पी एस यू को भूमि के हस्तांतरण आदि जैसे मुद्दों के कारण अन्य कारकों से क्षति हो रही है। एच ओ सी एल का उत्पादन जांच अवधि के दौरान बंद रहा था।
- ञ. रक्षोपाय शुल्क, यदि लगाया जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी और घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच पहले से मौजूद अंतर में और वृद्धि होगी। इससे संबंधित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और रोजगार तथा अनेक परिवारों की आजीविका दाव पर लग जाएगी।

ट. प्रयोक्ता आयातित फेनोल पर किसी अतिरिक्त लागत का वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। फेनोल की लागत में किसी वृद्धि से उसके घरेलू या आयातित होने पर विचार किए बिना केवल फेनोल की खपत में कमी होगी और उसके कीमत निर्धारण पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा

#### **घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस लिया जाना**

14. यद्यपि, महानिदेशक, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच की प्रक्रिया में थे और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे थे, तथापि, आवेदकों ने दिनांक 20 मार्च, 2020 और 23 मार्च, 2020 के अपने पत्रों द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने संबंधी अपने आवेदन को निम्नलिखित कहते हुए वापस ले लिया :

क. यह कि रक्षोपाय कानून का वर्तमान न्याय शास्त्र और व्याख्या भारत में फेनोल के बढ़े हुए आयातों का उपचार नहीं करती है।

ख. यह कि इसलिए आवेदक पाटनरोधी कानूनों के अंतर्गत उपचार की मांग करते हैं।

#### **महानिदेशक द्वारा जांच**

15. घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन को वापस लेने के संबंध में किए गए अनुरोध के मद्देनजर महानिदेशक के लिए जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए वास्तविक और विधिक अनुरोधों के उत्तर में उनके जांच परिणाम जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन, आवेदन को वापस लिए जाने के पश्चात निष्क्रिय हो गया है।

#### **निष्कर्ष**

16. चूंकि, आवेदकों ने आवेदन वापस ले लिया है, इसलिए वर्तमान जांच को जारी रखना उचित नहीं समझा जाता है। तदनुसार, आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध के मद्देनजर महानिदेशक, एतद्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 23/3/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई भारत में फेनोल के आयातों से संबंधित वर्तमान रक्षोपाय जांच को समाप्त करते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं महानिदेशक

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2020

**Case No. (SG) 03/2019**

**Subject : Safeguard investigation concerning imports of Phenol into India-Termination of the Investigation**

#### **F. No. 22/3/2019-DGTR.—A. Introduction**

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd (hereinafter referred to as “the Petitioners” or “the Applicants”) filed an application (petition) before the Director General in accordance with the Act and Rules supra for initiation of Safeguard investigation and imposition of Safeguard duties concerning imports of “Phenol” (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration) into India alleging increased imports of subject goods and consequent serious injury and threat of serious injury being caused by such increased imports of Phenol.

2. The Director General on the basis of *prima facie* evidence submitted by the Applicants, issued a public notice *vide* Notification No. 23/3/2019-DGTR dated 23<sup>rd</sup> August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject Safeguard investigation in accordance with the Rule 5 of the Rules, to determine whether as a result of unforeseen developments, the imports of the product under consideration constitute increased imports, and whether the increased imports have caused and/ or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like and/or directly competing products. As per initiation notification, Applicants constitute Domestic industry in terms of Clause (b) of the Sub Section (6) of Section 8B of the Custom Tariff Act, 1975.

### **B. Procedure**

3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the Notice of Initiation (NOI) dated 23rd August 2019 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Finance and the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, questionnaire were sent to foreign producers, exporters, importers and other domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.

4. In addition, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the notice of initiation.

5. In response to the initiation notification, following exporters/foreign producers and Government of exporting countries filed a questionnaire response:

- i. M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
- ii. Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs of the Republic of China (Taiwan)
- iii. M/s. Formosa Chemicals and Fibre Corporation
- iv. Kingdom of Saudi Arabia
- v. Embassy of the Federative Republic of Brazil
- vi. M/s. Kumho P&B Chemicals, Korea RP
- vii. Public Authority for Industry, State of Kuwait
- viii. M/s. Chang Chun Plastics Co. Ltd., Taiwan
- ix. Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India
- x. M/s. LG Chem Ltd.
- xi. Korea Petrochemical Industry Association
- xii. M/s. PTT Phenol Company Limited
- xiii. M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.
- xiv. M/s. Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd.
- xv. M/s. Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co. Ltd.
- xvi. Government of Indonesia
- xvii. M/s. Rhodia Poliamida e Especialidades S/A

6. The request to consider as an interested party and/or submissions/importer's questionnaire response was received from the following importers, users and their associations:

- a) M/s, Vinati Organics Limited
- b) M/s. Exim Corp
- c) M/s. Meghmani Organics Ltd.

- d) M/s. Versalis Spa
- e) M/s. Century Plyboards (India) Limited
- f) M/s. Rabigh Refining and Petrochemical Company
- g) M/s. Atul Ltd.
- h) M/s. CJ Shah and Co.
- i) M/s. Akin Chemicals Pvt. Ltd.
- j) M/s. Jupiter Dyechem Pvt. Ltd.
- k) M/s. Hazel Mercantile Limited
- l) M/s. Hareshkumar & Co.
- m) M/s. Haresh Petrochem Pvt. Ltd.
- n) Federation of Indian Plywood and Panel Industry
- o) Atul Ltd.,
- p) Meghmani Organics Ltd.

7. The period considered for the purposes of present investigation is 2016-17, 2017-18, 2018-19, April to June 2019 (Q1 of 2019-20). The applicants claimed surge in imports in Q1 2019-20.

8. The import volume provided in the Application for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 was based on Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) data but import volume for Q1 of 2019-20 was sourced from a secondary source. After initiation of investigation, the Authority procured the transaction-wise data from DGCI&S for the entire period considered for present investigation.

9. The non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file were kept open for inspection by the interested parties.

10. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Director General provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 4<sup>th</sup> December 2019. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.

11. Written submissions filed by one interested party were made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.

### **C. Submission by Domestic Industry**

12. The following submissions have been made by the Domestic Industry during the course of the investigation:

- a) Imports have increased under such conditions that the same has caused injury to the domestic industry.
- b) Factors such as imposition of ADD in China, Fresh capacities in China, Global oversupply, fresh capacities in India and US-China Trade issues have led to such increased imports.
- c) There is a significant decline in import prices of the subject goods.
- d) Imports of subject goods into India are in excess to the essential quantities as per the Demand of Phenol.
- e) The increased imports have an adverse effect on profitability, selling prices, inventories and sales of the Domestic Industry.
- f) Surge in imports with the steep fall in prices in the most recent period is threatening serious injury to the domestic industry.

**D. Submission by Other Interested Parties**

13. The following submissions have been made by other interested parties during the course of the investigation:

- a) The import volume provided in the petition for 2016-17, 2017-18 and 2018-19 is based on DGCI&S data but import volume for Q1 of 2019-20 has been sourced from an undisclosed 'secondary source' and is therefore not verifiable and is unreliable. The import volume of Phenol obtained from DGFT database reveals relatively much lower figures for Q1 of FY 2019-20. Therefore, there is no surge in imports to justify the initiation of Safeguard investigation on imports of the subject goods into India.
- b) It is a settled legal position that for safeguard investigations, increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough to cause or threaten to cause 'serious injury'. While on year to year basis there is an insignificant increase in imports of 1% as compared to 2016-17, there is a significant decline in imports between 2017-2018 and 2018-2019 amounting to 20%.
- c) There is no serious injury to the Domestic Industry. Most economic parameters show a positive trend and improvement in performance.
- d) None of the identified developments could be termed as "unforeseen" in terms of Article XIX(1)(a) of GATT. Mere imposition of trade remedy measures by major consumption markets such as China could not be termed as unforeseen.
- e) Application is incomplete as no adjustment plan has been provided by the Domestic Industry.
- f) Production, sales, installed capacity, capacity utilization, and employees of the domestic industry increased year on year. The domestic industry has also shown significant improvement in return on capital employed and profits.
- g) Any alleged injury suffered by Deepak Phenolics is due to teething issues and cannot be attributed to the subject imports. SI group, which in past has always participated in trade remedy investigations regarding Phenol and holds nearly 30% of the production in India is missing from this petition.
- h) Deepak Phenolics was not in existence for majority of the POI i.e. for 31 months of the POI. No proper assessment of injury can be made of the domestic industry, whose one of the constituents was not in existence for first 31 months of the POI.
- i) HOCL is suffering injury due to other factors for a very long time such as non-availability of working capital for continuous operation, lack of funds for modernization of plants, transfer of land to other PSU for settling liabilities etc. The production of HOCL was suspended during the POI.
- j) Safeguard duty, if imposed, would result in increase in prices and would fuel the already existing gap between domestic demand and supply. This would have an adverse effect on the connected industries and would put at stake the employment and livelihood of several families.
- k) The users are in no position to incur any extra cost on imported phenol. Any increase in the cost of phenol will only decelerate the consumption of phenol regardless of whether it is domestic or imported and dent its pricing further.

**E. Withdrawal of application by Domestic Industry**

14. While the Director General was in the process of examining all the issues raised by various interested parties, and making a conclusion on the basis of analysis, the Applicants vide their letters dated 20<sup>th</sup> March 2020 and 23<sup>rd</sup> March 2020 withdrew the application for imposition of safeguard duty stating:

- a. That the current jurisprudence and interpretation of Safeguard law does not remedy the increased import of Phenol into India,
- b. That the Applicants are, therefore, seeking remedy under the Anti-dumping laws.

**F. Examination by the Director General**

15. In view of the request made by the domestic industry withdrawing its application, there is no requirement for the Director General to issue its findings in response to the factual and legal submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation as the application filed by the domestic industry has become infructuous after the withdrawal of application.

**G. Conclusion**

16. Since the Applicants have withdrawn the application, it is considered appropriate not to continue with the present investigation. Accordingly, in view of the request made by the Applicants, the Director General, hereby, terminates the present Safeguard investigation concerning imports of “Phenol” into India initiated vide Notification No. 23/3/2019-DGTR dated 23<sup>rd</sup> August 2019.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Director General